

प्रेषक,

बी०एम० मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 5 अप्रैल, 2018

विषय:- जनपद चमोली में जोशीमठ जलोत्सारण योजना के अर्न्तगत विभिन्न स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु 0.990 है० भूमि को लीज पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पत्र संख्या-7951/छब्बीस-20(2011-12), दिनांक 21 जुलाई, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद चमोली में जोशीमठ जलोत्सारण योजना के अर्न्तगत विभिन्न स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु 0.990 है० भूमि परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रक इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को 30 वर्षों के लिए लीज पर आवंटित करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के शासनादेश संख्या-एल-642/14-3-627/89, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 में निहित व्यवस्थानुसार 1.0 है० से कम के प्रकरणों में रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की वर्ष 2018-19 की दर रू० 1100/- प्रति वृक्ष निर्धारित की गयी है अतः कुल-100 वृक्षों हेतु रू० 1,10,000/- की धनराशि की आवश्यकता होगी जो कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगी। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अनिवार्य रूप से चस्पा भी किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली में जोशीमठ जलोत्सारण योजना के अर्न्तगत विभिन्न स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु 0.990 है० भूमि शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-राजस्व-1, दिनांक 09 मई, 1984, शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1, दिनांक 12-09-1997 तथा शासनादेश संख्या-1115/XVII(II)/2016-18(184)/2015, दिनांक 15 जून, 2016 में निहित व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रक इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को 30 वर्षों के लिए लीज पर आवंटित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

- (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- (7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- (8) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्राण्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- (9) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (10) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या- 538/XVIII(II)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
- 6- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।